आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 18.04.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका।
- केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा– विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक अवसर गंवाया।
- राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे छात्रों को नई तकनीकों के प्रति जागरूक करें और उनके प्रभावी उपयोग के लिए सक्षम बनाएं।
- प्रदेश सरकार ने पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में उचित सुधार प्रबंधन करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

विधेयक

संविधान –131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून –संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सके। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पडे। विधेयक पारित होने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी। इस विधेयक के पारित न होने के कारण परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून–संशोधन विधेयक, 2026 सहित अन्य दो विधेयकों को पारित करने के लिए पेश नहीं किए गया। लोकसभा की बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधेयक पारित न होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने इस विधेयक का समर्थन न करके ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया है।

पश्चिम एशिया संकट

केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देशभर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि अब तक पांच किलो वाले 16 लाख 50 हजार से अधिक सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।

राज्यपाल

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा है कि 21वीं सदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों का युग है और इन्हें अपनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन तकनीकों का समावेश उत्तराखण्ड के छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। वे देहरादून में आयोजित "शिक्षा पर एआई के प्रभाव" कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे छात्रों को नई तकनीकों के प्रति जागरूक करें और उनके प्रभावी उपयोग के लिए सक्षम बनाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखण्ड के शिक्षक और छात्र मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात करेंगे।

राज्यपाल ने कहा कि एआई के माध्यम से शिक्षा को अधिक समावेशी बनाया जा सकता है। विशेष रूप से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने में यह सहायक सिद्ध होगा। साथ ही, एआई भाषा की बाधाओं को दूर कर स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को सशक्त बनाने का अवसर भी प्रदान करता है।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में देहरादून शहर के यातायात संतुलन को लेकर देहरादून गतिशील प्लान की बैठक ली।

मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून – दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर के बन जाने से सप्ताहांत एवं चारधाम यात्रा के कारण अत्यधिक यातायात दबाव रहेगा, इसके लिए उन्होंने लगातार देहरादून के यातायात व्यवस्था में उचित सुधार प्रबंधन करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा आढ़त बाज़ार की रजिस्ट्री एवं मुआवजा का कार्य को आगामी 15 मई पूरा किए जाने पर जोर दिया। साथ ही निरंजनपुर मंडी को भी शीघ्र शुरू कराए के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित करने के लिए तत्काल एक साईट सिलेक्शन कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए।

विमोचन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई आगामी 05 वर्षों 2026–2031 के कार्यों से संबंधित मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया।

आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा आगामी 05 वर्षों के विजन पर आधारित मास्टर प्लान पुस्तिका का विमोचन किया जाना सराहनीय पहल है। यह पुस्तिका राज्य में बुनियादी ढांचे को विकसित करने, सशक्त और सुरक्षित, भविष्य को सुनिश्चित करने का मार्ग है। उन्होंने कहा राज्य में विकास की संभावनाओं एवं विकसित भारत 2047 के संकल्पों को पूरा करने में यह मास्टर प्लान पुस्तिका अहम भूमिका निभाएगी।

नशा मुक्त

पिथौरागढ़ में नशा मुक्त समाज और बाल विवाह की रोकथाम पर प्रशासन सख्त हो गया है। जिले में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और बाल विवाह की घटनाओं को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

बैठक में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास समेत संबंधित विभागों को समन्वय के साथ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि नशे के खिलाफ गांव गांव में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और स्कूल–कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने के सभी को विशेष निर्देश दिए गए हैं।

फुटबॉल प्रतियोगिता

खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत अस्मिता अंडर–16 बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बागेश्वर जिले के नुमाइश खेत मैदान में किया गया। प्रतियोगिता में 6 टीमों ने प्रतिभाग किया।

प्रतियोगिता के बारे में जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव नीरज पांडे ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है।

'स्कूल से सड़क तक हरियाली'अभियान

देहरादून जिला प्रशासन ने पर्यटन नगरी मसूरी को अधिक सुंदर, व्यवस्थित और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य से 'स्कूल से सड़क तक हरियाली' अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी राहुल आनंद की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।

उन्होंने स्कूल प्रबंधन से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह वे अपने परिसरों को स्वच्छ और हरा–भरा रखते हैं, उसी प्रकार स्कूल के बाहर की सड़कों, दीवारों और आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित करें।

उच्च न्यायालय

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर नियुक्ति के लिए चयन मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी से प्रत्यावेदन देने और कमीशन उस प्रत्यावेदन पर कानून के मुताबिक चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।